

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद की पत्रकार वार्ता का संशोधित  
प्रतिलेख: 8 अगस्त, 2024

**भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिभागी:**

- श्री शक्तिकांत दास - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
डॉ. माइकल डी. पात्रा - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
श्री एम. राजेश्वर राव - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
श्री टी. रबी शंकर - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
श्री स्वामीनाथन जे. - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक  
डॉ. ओ. पी. मल्ल - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक  
डॉ. राजीव रंजन - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

**संचालक:**

श्री पुनीत पंचोली - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

**पुनीत पंचोली:**

नमस्कार। मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद की इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ गवर्नर - श्री शक्तिकांत दास; उप गवर्नर - डॉ. एम.डी. पात्रा; श्री एम. राजेश्वर राव; श्री टी. रबी शंकर; और श्री स्वामीनाथन जे. उपस्थित हैं। हमारे साथ कार्यपालक निदेशक - डॉ. ओ.पी. मल्ल और डॉ. राजीव रंजन तथा रिज़र्व बैंक के कुछ अन्य सहयोगी भी मौजूद हैं। महोदय, परंपरा के अनुसार, मैं आपसे अपने उद्घाटन उद्बोधन देने का अनुरोध करता हूँ, जिसके पश्चात हम प्रश्न-उत्तर सत्र की ओर बढ़ेंगे।

**शक्तिकांत दास:**

सभी को पुनः एक बार सुप्रभात और नमस्कार। मेरे पास सात बिंदु हैं, जो मुख्य रूप से उस विवरण से लिए गए हैं जो मैं पहले ही दे चुका हूँ, और ये अत्यंत संक्षिप्त हैं:

- घरेलू आर्थिक विकास लचीला है।
- मुद्रास्फीति अपने पूर्व उच्च स्तरों से मध्यम हुई है, लेकिन अवस्फीति की गति असमान और धीमी है।
- हालांकि, मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के साथ समान करने के लिए अभी कुछ दूरी तय करनी शेष है।
- वित्तीय क्षेत्र स्थिर है, जिसका तुलनपत्र अच्छी तरह से पूंजीकृत और सुचारु है।
- भारत ने बाहरी झटकों के प्रसार-प्रभावों के प्रति अपनी लचीलेपन की क्षमता को बढ़ाया है।
- विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक उच्च स्तर 675 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

- रिज़र्व बैंक अपने विनियामक क्षेत्र में वित्तीय बाजारों के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

धन्यवाद।

### पुनीत पंचोली:

धन्यवाद महोदय। शुरू करने से पहले, मैं यहां उपस्थित मीडिया के मित्रों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। साथ ही, कृपया प्रति व्यक्ति केवल एक प्रश्न तक सीमित रहें ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। यदि समय अनुमति दे, तो हम अन्य प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं। महोदय, आज मीडिया से 24 प्रतिभागी हैं, और आपकी अनुमति से, मैं उनके नाम पुकारूंगा। अतः हम सीएनबीसी-टीवी18 की सुश्री लता वेंकटेश से शुरू करेंगे।

### शक्तिकांत दास:

इससे पहले मैं केवल एक बिंदु रखना चाहता हूं। दूसरे बिंदु के संबंध में, वास्तव में मैंने जो कहा था उसे पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। इसे इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि 'मुद्रास्फीति मध्यम हो रही है, लेकिन अवस्फीति की गति असमान और धीमी है।' पहले मैंने कहा था कि यह अपने उच्च स्तरों से मध्यम हो गई है, लेकिन वास्तविक शब्दावली यह होनी चाहिए कि मुद्रास्फीति मध्यम हो रही है, लेकिन विनिद्रास्फीति की गति असमान और धीमी है। और तीसरा बिंदु यह था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए अभी कुछ दूरी तय करनी शेष है। धन्यवाद। कृपया आगे बढ़ें।

### लता वेंकटेश, सीएनबीसी-टीवी:

सुप्रभात गवर्नर महोदय और आरबीआई के सभी सदस्य। मैं सीएनबीसी-टीवी18 से लता वेंकटेश हूं। गवर्नर महोदय, क्या आप वैश्विक, विशेष रूप से अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं? पिछले एक सप्ताह में यह अपेक्षा की जा रही थी कि सितंबर 2024 में फेड द्वारा ब्याज दरों में एक कटौती की जाएगी। अब बाजार 125 आधार अंक की कटौती की संभावना को भांप रहा है। जबकि हम पूरी तरह से समझते हैं कि आप विदेशी अर्थव्यवस्था की स्थिति चाहे जैसी भी हो, घरेलू अर्थव्यवस्था के अनुसार नीति निर्धारित करेंगे, फिर भी इसका वैश्विक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। अतः, यदि वास्तव में ऐसा होता है कि फेड को 5 कटौतियां करनी पड़ें और वहां मंदी आती है, तो क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि क्या आपको हमारे विकास और मुद्रास्फीति में कोई गिरावट का रुख दिखाई देता है? इसके अतिरिक्त, एक अनुरोध है कि क्या आप अब नाममात्र पूर्वानुमान भी प्रदान नहीं कर सकते?

## शक्तिकांत दास:

नहीं, वह (नाममात्र विकास पूर्वानुमान) एक अलग मुद्दा है। मेरा अनुमान है कि इस विषय पर कुछ अन्य प्रश्न भी आएंगे क्योंकि यह सभी के मन में ताजा है। अतः, हम वास्तव में इस मुद्दे पर काफी प्रश्नों की अपेक्षा कर रहे थे। तो, क्या इस विशेष क्षेत्र या संबंधित क्षेत्र पर कोई प्रश्न पूछना चाहता है ताकि हम सभी को एक साथ ले सकें? नहीं, लगता है नहीं। ठीक है, वही प्रश्न।

देखिए, कुछ घटनाएं हुईं, आप संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था का उल्लेख कर रहे थे। वास्तव में, यदि आप देखें, तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली यह कि संयुक्त राज्य अमेरिका से पिछले सप्ताह जो बेरोजगारी का आंकड़ा आया है, उसने इस प्रकार की अटकलें लगाई हैं। लेकिन यदि आप अमेरिका में समग्र आर्थिक विकास को देखें, तो मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दूसरी तिमाही के विकास के आंकड़े पहली तिमाही से अधिक थे और यह लगभग 2.8% था। दूसरी बात यह है कि जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, यह केवल एक महीने का आंकड़ा है। केवल एक महीने के आंकड़े के आधार पर, आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी या मंदी की संभावना के बारे में निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते और न ही जल्दबाजी कर सकते हैं। अतः आपको आने वाले आंकड़ों की प्रतीक्षा करनी होगी। किसी भी स्थिति में, मुझे लगता है कि फेड के कई सदस्यों से जो कथा निकल रही है, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें निगरानी करने की आवश्यकता है। अतः, इसलिए मैं कहूंगा कि इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी की बात करना समय से पहले होगा। लेकिन मैं अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहा हूँ और रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण से मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम घरेलू और इस मामले में बाहरी स्रोतों से आने वाले सभी आंकड़ों पर सतर्क रहेंगे, और हम सभी उभरती स्थितियों से निपटेंगे।

इसके अतिरिक्त, मुझे यह भी जोड़ने दें और यह मेरे विवरण में और उन बिंदुओं में भी है जो मैंने अभी पढ़े हैं। आज, भारत ने बाहरी झटकों के प्रति अपनी लचीलापन क्षमता को काफी हद तक बेहतर बनाया है। मुझे लगता है कि भारत पहले की तुलना में कहीं अधिक लचीला है। अतः हमें आने वाले आंकड़ों की प्रतीक्षा करनी होगी और स्थिति से निपटना होगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे आईएमएफ, ओईसीडी, डब्ल्यूटीओ, सभी ने इस वर्ष वैश्विक व्यापार में वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष की बहुत कम वृद्धि के मुकाबले लगभग 3% रहेगा। अतः, यह अनुमान बहुत हाल ही में लगाया गया था और यह स्पष्ट रूप से समग्र बाहरी मांग की स्थिति का समर्थन करेगा। अतः, मैं यहीं विराम देता हूँ।

## पुनीत पंचोली:

धन्यवाद महोदय। क्या मैं इकोनॉमिक टाइम्स की सुश्री संगीता मेहता से अनुरोध कर सकता हूँ? यदि आप प्रश्न पूछना चाहें।

**संगीता मेहता, द इकोनॉमिक टाइम्स:**

धन्यवाद महोदय। अतः, आपने अपनी नीति में उल्लेख किया था कि आप मुद्रास्फीति पर सतर्क रहेंगे और यह भी कहा था कि आप उपाय इस बात पर निर्भर करेंगे कि यह क्षणिक है या स्थायी। तो, आप निष्कर्ष निकालने के लिए क्योप उपाय अपनाएंगे? मेरा अभिप्राय यह है कि आप यह निष्कर्ष निकालने के लिए कौन से मापदंडों का उपयोग करेंगे कि मुद्रास्फीति क्षणिक है और स्थायी नहीं है? आरबीआई के मन में कौन से उपकरण या उपाय हैं?

**माइकल डी. पात्रा:**

सबसे पहले, हम झटकों के स्रोतों को देखते हैं। खाद्य श्रेणी में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार होते हैं; उनमें से कुछ 7-दिवसीय आवृत्ति वाले होते हैं, जो अत्यंत शीघ्र नष्ट होने वाले होते हैं, और कुछ 30-दिवसीय आवृत्ति वाले होते हैं, जो थोड़े अधिक समय तक रहते हैं। अतः, आम तौर पर, अत्यंत शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं में झटका बहुत कम अवधि का होता है जो दो महीने से अधिक नहीं रहता। इसके अलावा, हम 'स्थायित्व' की गणना कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि झटके के बाद किसी विशिष्ट मूल्य को अपने औसत मूल्य तक वापस लौटने में कितना समय लगता है। अतः, जब हम यह आंकलन करते हैं कि मुद्रास्फीति स्थायी है या क्षणिक, तब हम इन सभी पहलुओं पर नजर रखते हैं।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। अगला प्रश्न, हम टाइम्स ऑफ इंडिया के श्री मयूर शेटी को देंगे।

**मयूर शेटी, टाइम्स ऑफ इंडिया:**

एक अध्ययन था जिसमें कहा गया था कि तटस्थ ब्याज दर बढ़ गई है और हाल ही में आपने एलसीआर के माध्यम से बैंकों के लिए चलनिधि आवश्यकताओं को बढ़ाया है। अतः, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ब्याज दरों और चलनिधि के मामले में कोई 'नया सामान्य' आ गया है जो पहले से अधिक है? और इस पर एक अनुवर्ती प्रश्न यह है कि आपने बैंकों से अधिक घरेलू जमाराशियां जुटाने को कहा है। तो, क्या यह संकेत है कि जमा दरों में वृद्धि होनी चाहिए?

**शक्तिकांत दास:**

देखिए, एलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात) के संबंध में, जिसे बैंकों को बनाए रखने की अपेक्षा है, यह एक मसौदा है जिसे हमने सार्वजनिक डोमेन में रखा है। हमें सभी हितधारकों, जिनमें बैंक और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं, से इनपुट प्राप्त होंगे। उसके आधार पर, हम निर्णय लेंगे। अब तक यह कहना उचित नहीं होगा कि हमने चलनिधि आवश्यकताओं को बढ़ाया है क्योंकि यह अभी भी विचाराधीन है। अब, जहां तक जमा दरों का प्रश्न है, यह इन मामलों पर निर्णय लेना व्यक्तिगत बैंकों का है, जो पूरी तरह से उनके वाणिज्यिक निर्णय लेने का हिस्सा

है। जैसा कि आप जानते हैं, उधार दरें और जमा दरें विनियमन-मुक्त हैं। यह बैंकों पर निर्भर है और स्थिति बैंक से बैंक में भिन्न होगी। अतः, समग्र आर्थिक स्थिति, वित्तीय शर्तों, और व्यक्तिगत बैंकों की अपनी आंतरिक स्थिति—जैसे कि उनके पास कितनी जमाराशियां हैं, उनकी जमाराशियों का संघटन क्या है, और उनका ऋण विकास क्या है—के आधार पर जमा दरों पर निर्णय लेना बैंकों का है और बैंकों को ही इस पर ध्यान देना होगा। हमने केवल इतना कहा है कि बैंकों को अपने शाखा नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए और जमाराशियां जुटाने के संबंध में नवाचारी उत्पाद पेशकश लानी चाहिए। अतः, यह बैंकों के लिए है कि वे निर्णय लें। तटस्थ दर के संबंध में, मैं उप गवर्नर, माइकल पात्रा से इस प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

**माइकल डी. पात्रा:**

हां। तो, जैसा कि हमने वचन दिया था, हमने तटस्थ दर के अद्यतन अनुमान जारी किए हैं और जैसा कि हमने संदेह किया था, तटस्थ दर वास्तव में अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन को दर्शा रही है। तटस्थ दर का प्रमुख चालक संभावित विकास है और वह बढ़ना शुरू हो गया है। अतः, यदि आप तटस्थ दर को ध्यान में रखें, तो आप देखेंगे कि नीतिगत दर का वर्तमान स्तर संभवतः बिल्कुल सही है। और चलनिधि के प्रश्न के संबंध में जो आपने पूछा, चलनिधि संचालन प्रक्रिया है। यह केवल नीतिगत रवैये को दर्शाती है। यह स्वयं में स्वतंत्र नहीं है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। अगला, हम थॉमसन रॉयटर्स की सुश्री स्वाति भट्ट को प्रश्न देंगे।

**स्वाति भट्ट, थॉमसन रॉयटर्स:**

धन्यवाद। गवर्नर महोदय, मेरे पास विदेशी धन के प्रवाह के संबंध में दो अत्यंत संबंधित प्रश्न हैं। पहला, हमने देखा कि सरकार एफएआर प्रतिभूतियों पर पिछले कदम से हट गई और आरबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी की जिसे बाजार सहभागियों ने एफएआर के तहत 14-वर्षीय और 30-वर्षीय बॉन्ड्स की अनुमति देने पर ली गई एक 'यू-टर्न' कहा। अब, आज हमने देखा है कि 10-वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड में विदेशी स्वामित्व 9.6% तक पहुंच गया है। क्या बेंचमार्क प्रतिभूतियों में इतने अधिक स्वामित्व से चिंता का विषय बनने जा रहा है, क्योंकि यह अब तक की सबसे लंबी अवधि वाला बॉन्ड है जिसमें विदेशी निवेशक स्वतंत्र रूप से निवेश कर सकते हैं? और क्या एफएआर प्रतिभूतियों पर पहले से घोषित किए गए कदमों से परे पुनर्विचार की संभावना है? और दूसरा, ओआईएस के मामले में भी, विदेशियों के लिए घरेलू बाजार में पोजीशन लेने की सीमा 350 करोड़ रुपये है, जो लगभग समापन के कगार पर है। क्या उस पर पुनर्विचार किया जाने की संभावना है, क्योंकि अन्यथा हम इस बाजार को ऑफशोर ओआईएस बाजारों (एनडी-ओआईएस की ओर धकेल सकते हैं?)

### शक्तिकांत दास:

में सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया केवल एक प्रश्न पूछें, ताकि सभी को अवसर मिल सके। मुझे लगता है कि आप (उप गवर्नर, मौद्रिक नीति विभाग) प्रश्न का उत्तर दें।

### माइकल डी. पात्रा:

तो, स्वाति, यदि आप कुल बकाया (जी-सेक) को देखें। कुल बकाया 10-वर्षीय पेपर में, विभिन्न मार्गों के तहत कुल विदेशी होल्डिंग (एफपीआई) केवल 4.8% बकाया है। अब यदि आप एमटीएफ (मध्यम-अवधि ढांचा) को देखें, तो उसमें प्रतिभूति-वार होल्डिंग, एफपीआई-वार होल्डिंग और एकाग्रता सीमाओं पर निश्चित सीमाएं हैं। अतः, वहां किसी भी अस्थिरता के लिए ये प्राकृतिक बाधाएं हैं, है न? एफएआर से प्रतिभूतियों को बाहर रखने के प्रश्न पर, हमने देखा है कि एफएआर निवेशकों की रुचि का प्रमुख हिस्सा 5 से 10 वर्ष के पेपर में है। वास्तव में, यह कुल निवेश का 90% हिस्सा है और 30-वर्षीय में रुचि केवल 30-वर्षीय के कुल स्टॉक का 2% है। यह एक मुद्दा रहा है। अतः, यह एक बात हुई। इसके अलावा, यह लोगों को अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करने के लिए समय देने जैसा है क्योंकि हमें पता है कि बॉन्ड इंडेक्स में भारत का भार 10 महीने की अवधि में धीरे-धीरे बढ़ेगा। उनके पास अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करने का समय है। अब जारी किए गए सभी मौजूदा प्रतिभूतियां एफएआर निवेशों के लिए उपलब्ध हैं, जिससे 41 लाख करोड़ रुपये का निवेश उपलब्ध होता है, जिनमें से आज केवल 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश है। अतः, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह है। हमारा आंकलन है कि जिन श्रेणियों को अब अनुमति दी गई है, उनमें 4 लाख करोड़ रुपये के नए जारीकरण होंगे जो एफएआर के लिए खुले होंगे। इसके अलावा, एमटीएफ है जिस पर सीमा 6% है, लेकिन आज यह केवल 2% है। अतः, यह उतना भयानक नहीं है जितना बनाया जा रहा है। और जो होगा वह यह है कि हमारी उम्मीद है कि उन्हें इस 5 से 10 वर्ष के खंड में केंद्रित करने से वास्तव में यह अधिक चलनिधीय होगा, बेहतर मूल्य निर्धारण होगा, और गहराई बढ़ने के साथ लेन-देन लागत कम होगी। आपका (दूसरा) प्रश्न क्या था?

### स्वाति भट्ट, थॉमसन रॉयटर्स:

अतः, 350 करोड़ रुपये की सीमा लगभग समाप्त होने के कगार पर है। इसे 2019 में निर्धारित किया गया था और इसकी कोई समीक्षा नहीं हुई है। अतः, यदि इन एफपीआई को ब्याज दरों पर अपनी शर्तों को हेज करना है, तो उन्हें अब ऑफशोर जाना पड़ सकता है। तो, क्या उस 350 करोड़ रुपये की सीमा में कोई वृद्धि होने वाली है?

**माइकल डी. पात्रा:**

हम इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही यह भी याद रखें कि हम पूंजी खाते पर पूरी तरह से खुले नहीं हैं। अतः, यह उसी का एक हिस्सा है। जैसे-जैसे सीमा के निकट पहुंचा जाएगा, हम इसकी समीक्षा करेंगे।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। अगला, हम ब्लूमबर्ग के श्री अनुप रॉय को प्रश्न देंगे।

**अनूप रॉय, ब्लूमबर्ग:**

महोदय, आपने आज सुबह खाद्य मुद्रास्फीति और इसके महत्व के बारे में बात की थी। लेकिन सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य से बाहर छोड़ दिया जाना चाहिए और वे कुछ तर्कों के साथ यह भी कह रहे हैं कि मौद्रिक नीति खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकती। उपभोग व्यय सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि सीपीआई में खाद्य का भार संभवतः कम हो रहा है। तो, क्या आप सीपीआई में बदलाव चाहेंगे और क्या यह आपके लिए लक्ष्य हासिल करने का सही मानदंड है?

**शक्तिकांत दास:**

देखिए, उपभोग व्यय सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान सीपीआई बास्केट और इसमें कोर, ईंधन और खाद्य का भार कितना है, यह 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर तय किया गया था। कई वर्ष बीत गए हैं। मेरा अनुमान है कि कोविड और महामारी से जुड़े तनाव के कारण एक और समीक्षा नहीं की जा सकी। जहां तक मुझे ज्ञात है, एनएसओ द्वारा एक वर्ष का आंकड़ा संग्रहण किया जा चुका है। मुझे लगता है कि अगले वर्ष का आंकड़ा संग्रहण चल रहा है और विश्लेषण भी चल रहा है। अतः, इसके आधार पर एनएसओ निर्णय लेगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय-समय पर की जाती है। हम यह देख रहे हैं कि एनएसओ क्या करता है, जो वास्तव में उपभोग बास्केट का आधार है, और हम अपना निष्कर्ष उसी से निकालते हैं। देश भी वहीं से आंकड़े लेता है। कुल व्यय बास्केट में क्या है, खाद्य घटक कितना है, कोर घटक कितना है, और ईंधन घटक कितना है? अतः, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के इन सभी घटकों के भार के संबंध में अब तक कोई निश्चित निष्कर्ष सामने नहीं आया है।

और खाद्य मुद्रास्फीति के महत्व के संबंध में, किसी भी सामान्य व्यक्ति या व्यवसायी के मन में यह प्रश्न आता है कि खाद्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में मौद्रिक नीति की क्या भूमिका है। ऐसा प्रस्तुत किया जाता है मानो मौद्रिक नीति की कोई भूमिका ही न हो। अतः, मूल रूप से, जो कुछ मैं कहना चाहता था, वह मैंने अपने वक्तव्य में कह दिया है। मैंने जो अपने वक्तव्य में कहा है, उसमें जोड़ने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। मैं बिजनेस टुडे के श्री आनंद अधिकारी से अनुरोध करूंगा।

**आनंद अधिकारी, बिजनेस टुडे:**

नमस्कार महोदय। महोदय, बाजार में एक कहानी सी प्रचलित है कि एफएंडओ ट्रेडिंग घरेलू बचतों को प्रभावित कर रही है। मैं वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों में फंड प्रवाह पर कुछ आरबीआई के आंकड़े देख रहा था। यह वित्त वर्ष 2023 के लिए है। इसमें इक्विटी ट्रेडिंग का हिस्सा नगण्य है, म्यूचुअल फंड का हिस्सा बहुत अधिक है, और एफडी, पीएफ और बीमा का हिस्सा कहीं अधिक है। दूसरा, वित्तीय देनदारियां बढ़ी हैं, लेकिन यह वृद्धि व्यक्तिगत ऋण के कारण नहीं, बल्कि आवास या गृह ऋण के कारण हुई है। अतः, क्या घरेलू बचत में गिरावट को एफएंडओ ट्रेडिंग से जोड़ना उचित है?

**शक्तिकांत दास:**

नहीं, हम (घरेलू बचतों को एफएंडओ ट्रेडिंग से) नहीं जोड़ रहे हैं।

**आनंद अधिकारी, बिजनेस टुडे:**

मैं कह रहा हूं कि यह बाजार में प्रचलित एक कथा है जो इसे जोड़ रही है।

**शक्तिकांत दास:**

बाजार में कुछ कथाएं हैं! क्या आप (महानिदेशक, मौद्रिक नीति विभाग) इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे?

**माइकल डी. पात्रा:**

अतः, मैं अनुरोध करूंगा कि आप घरेलू बचतों को एक थोड़े अलग दृष्टिकोण से देखें। जैसा कि आपने सही कहा, घरेलू बचतों के संघटन में इक्विटी का बहुत अधिक जोखिम नहीं दिखता। वास्तव में जो हो रहा है वह यह है कि एक मंथन चल रहा है। कोविड के दौरान की गई सावधानीपूर्ण बचतों में वित्तीय बचतें बहुत अधिक थीं क्योंकि खर्च करने के कोई रास्ते नहीं थे। अब उन्हें वापस अधिक सामान्य स्तर पर लाया जा रहा है। अतः, घरेलू बचत का एक पहलू यह है। दूसरा पहलू यह है कि वित्तीय बचत से भौतिक बचत की ओर एक स्थानांतरण हो रहा है। लोग अधिक घर आदि खरीद रहे हैं। अतः भौतिक बचत वास्तव में बढ़ रही है। यदि आप दोनों को एक साथ लें, तो कुल घरेलू बचत लगभग 20% पर स्थिर हो गई है। यह काफी समय से गिर रही थी, और अब यह स्थिर हो गई है। अतः, कुल मिलाकर, मैं इन बदलावों के साथ घरेलू बचत व्यवहार में सामान्य स्थिति की वापसी देख रहा हूं।

### पुनीत पंचोली:

धन्यवाद महोदय। अगला, मैं ईटी नाउ के श्री अंकुर मिश्रा से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा।

### अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

अतः, उसी प्रश्न को जारी रखते हुए, आपने पहले भी उल्लेख किया था कि विशेष रूप से एफएंडओ के संबंध में, बढ़ते वॉल्यूम को आप वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब आज की नीति वक्तव्य में भी आपने धन के वैकल्पिक निवेश मार्गों की ओर जाने का उल्लेख किया है। सेबी ने हाल ही में एफएंडओ पर एक परामर्श पत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य प्रवेश स्तर के उस खुदरा भागीदारी को प्रतिबंधित करना है जो पैसा खो रही है और सेबी के आंकड़ों के अनुसार, यह लगभग 90% है। अतः, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे कदमों से बैंकों की उस दिशा में मदद होगी जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि जमाराशियां जुटानी आवश्यक हैं और नवोन्मेषी तरीकों की आवश्यकता है? क्या ये कदम बैंकों को जमाराशियां जुटाने में मदद करेंगे?

### शक्तिकांत दास:

देखिए, एफएंडओ में, लोग केवल मार्जिन को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी बचत राशि एफएंडओ में जा रही है। अतः, यह बात हमें याद रखनी होगी। और एफएंडओ पर जो भी हमारे विचार थे, उन्हें हमने सभी नियामकों के बीच मौजूद 'पूर्व संकेतक दल' (अर्ली वार्निंग ग्रुप) में सेबी के साथ चर्चा की है। इस पर चर्चा हुई है; हमने अपने दृष्टिकोण वहां रखे हैं। सेबी ने हमारे दृष्टिकोणों को नोट किया है। सेबी ने अपना विश्लेषण किया है, और चर्चा पत्र और उन्हें मिलने वाले इनपुट के आधार पर सेबी उचित कार्रवाई करेगी। और बैंक जमाराशियों के संबंध में, मुझे लगता है कि उप गवर्नर (मौद्रिक नीति विभाग) ने पहले ही इसकी व्याख्या कर दी है। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ उसका सार यह है कि बैंक जमाराशियों और बैंक ऋण वृद्धि के बीच असंतुलन या विचलन से संपत्ति-देनदारिता या चलनिधि प्रबंधन के मुद्दे पैदा हो सकते हैं। अतः, मैं केवल इस मुद्दे की ओर इशारा कर रहा हूँ कि जमाराशियों की वृद्धि बनाम ऋण वृद्धि में इस विचलन के कारण, चलनिधि प्रबंधन का मुद्दा पैदा हो सकता है जिससे बैंकों को निपटना होगा। मैं किसी भी प्रकार यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि लोगों को जमाराशियां बैंकों में स्थानांतरित करनी चाहिए और इक्विटी बाजार में नहीं जाना चाहिए। यह लोगों, निवेशक और बचतकर्ता पर छोड़ दिया गया है कि वह अपना पैसा कहां लगाना चाहता है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि बैंकों को इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, इससे सजग रहना होगा, क्योंकि यह संभावित रूप से चलनिधि प्रबंधन के संबंध में कुछ संरचनात्मक चुनौतियां पैदा कर सकता है। और इस स्थिति से निपटने का एक तरीका यह है कि बैंकों के

पास अपनी शाखाओं का विशाल नेटवर्क है जिसका वे पूंजीकरण कर सकते हैं और अपनी जमाराशियों के स्तर को बढ़ा सकते हैं, यदि वे अपने ऋण वृद्धि को बनाए रखने और समर्थन देने का प्रस्ताव रखते हैं। अतः, यह अधिकतर उस संरचनात्मक चुनौती के संदर्भ में है जो चलनिधि प्रबंधन के संबंध में उत्पन्न हो सकती है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। अब मैं ईटी नाउ स्वदेश के अनुराग शाह से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा।

**अनुराग शाह, ईटी नाउ स्वदेश:**

धन्यवाद महोदय, मुझे प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए। महोदय, जैसा कि आपने कहा है कि बैंकों को जमाराशियों के संबंध में अपने नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए और नवोन्मेषी उत्पाद पेश करने चाहिए। मैं आपको मुंबई के एक बैंक का उदाहरण देता हूँ जिसने पूरे मुंबई में बैनर और पोस्टर लगाए हैं कि राज्य सरकार की एक योजना है जिसके तहत शून्य शेष खाता खोला जा सकता है, और वे बड़ी संख्या में खाते खोल रहे हैं। ऐसी योजना के तहत, सीमांत या गरीब लोग खाते खुलवाते हैं और फिर ये खाते केवल साइबर धोखाधड़ी के लिए उपयोग होने वाले 'म्यूल अकाउंट' (फर्जी/ठगी वाले खाते) बन जाते हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि अब प्रत्येक खाते का केवाईसी होता है, फिर भी पीड़ित अपनी रकम वापस नहीं पा पा रहे क्योंकि वे पहचान स्थापित नहीं कर पा रहे। अतः महोदय, जब हम असाधारण नवोन्मेषी उत्पादों की ओर बढ़ते हैं, तो क्या आरबीआई इस पर भी नजर रख रहा है?

**शक्तिकांत दास:**

मैं किसी को भी असाधारण कदम उठाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बैंकिंग प्रणाली के विनियामक मानदंड होते हैं। एक बैंक वही करेगा जो इन विनियामक मानदंडों के अंतर्गत संभव हो। हम किसी को भी नियमों से हटकर काम करने का संकेत नहीं दे रहे हैं और बैंक भी ऐसा नहीं करेंगे। और जहां तक जमाराशि जुटाने का प्रश्न है, मैं उस विशिष्ट मामले के बारे में बात नहीं करना चाहता जिसका आपने उल्लेख किया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे, हम व्यक्तिगत मामलों पर टिप्पणी नहीं करते। पिछले कुछ वर्षों में, बैंकों के अभिशासन मानकों और जोखिम प्रबंधन मानकों में बहुत सुधार हुआ है। अतः, यदि बैंक नए नवोन्मेषी उत्पाद शुरू करते हैं या नई मुहिम चलाते हैं, तो हमारा विश्वास है कि वे यह निर्णय इस बात के सावधानीपूर्वक आकलन के आधार पर लेंगे कि किस प्रकार के जोखिम हो सकते हैं।

**पुनीत पंचोली:**

अब मैं जी बिजनेस के श्री ब्रजेश कुमार को आमंत्रित करता हूँ।

**ब्रजेश कुमार, जी बिजनेस:**

महोदय, जैसा कि आपने कहा है कि बैंकों को अपने टॉप-अप ऋणों (ऋण के अतिरिक्त ऋण) के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए क्योंकि किसी को भी अंतिम उपयोग के बारे में पता नहीं होता। क्या आप संकेत दे रहे हैं कि ये सद्वागत गतिविधियों या अनुत्पादक क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं? और मैं यह भी समझना चाहता हूँ कि क्या यह संकेत है कि आप इस मामले पर विनियामक दिशानिर्देश लाने जा रहे हैं? आपने 2015 में सेवा शुल्क पर एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था, तो क्या कोई संभावना है कि आप उस सर्कुलर की समीक्षा करेंगे?

**शक्तिकांत दास:**

मैं आपका पहला प्रश्न लूंगा क्योंकि अधिक प्रश्न लेने का समय नहीं है। हालांकि, मैं आपके अन्य प्रश्नों का उत्तर द्विपक्षीय रूप से दे दूंगा। पहला प्रश्न टॉप-अप ऋण के बारे में था। अतः, यदि आप मेरे उस वक्तव्य को देखें जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, तो मैंने कहा है कि 'कुछ संस्थाओं' में हम देख रहे हैं कि वे टॉप-अप ऋणों के लिए विनियामक आवश्यकताओं का पालन नहीं कर रही हैं। मैंने केवल वही दोहराया है जो हमने वेबसाइट पर अपलोड किया है। अतः, यह प्रणाली स्तर की समस्या नहीं है, बल्कि कुछ संस्थाओं की समस्या है जिनके साथ हम द्विपक्षीय रूप से निपट रहे हैं। लेकिन यह एक प्रणालीगत समस्या नहीं है। चूंकि हमने कुछ संस्थाओं में एक प्रकार का रुझान देखा है, इसलिए हमने सभी बैंकों को यह संदेश दिया है कि आप उस पहलू पर ध्यान दें, क्योंकि बैंकों के पास देश भर में इतनी अधिक शाखाएं हैं। हमने बैंकों को ऋण के अंतिम उपयोग की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनियामक और सावधानीपूर्ण मानदंडों का पालन नीचे तक के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है या नहीं, यह सलाह दी है। यह एक सलाहकार प्रकृति का संचार था। और जहां भी हमने इसका पता लगाया है, जो कि केवल कुछ संस्थाओं में है, वहां हम अलग से निपट रहे हैं।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। अगला, हमारे पास बिजनेस स्टैंडर्ड के श्री मनोजित साहा हैं।

**मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:**

शुभ अपराह्न, महोदय। अपने वक्तव्य में, आपने कहा है कि मुद्रास्फीति में कमी (अवस्फीति) की प्रक्रिया असमान है, मुख्य रूप से बड़े और लगातार आपूर्ति झटकों के कारण, विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं के कारण। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि सरकारी एजेंसियां आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन की निगरानी किस प्रकार कर रही हैं? क्या हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि

वे अपने आपूर्ति प्रबंधन में सुधार करेंगे ताकि लक्ष्य की ओर मुद्रास्फीति में कमी की प्रक्रिया अधिक सुचारू हो सके?

**शक्तिकांत दास:**

आपूर्ति पक्ष के उपायों के पहलू पर, आरबीआई और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के बीच निरंतर संवाद बना रहता है। और सरकार ने कई उपाय किए हैं। वास्तव में, पिछले वर्ष वार्षिक रिपोर्ट में हमने उन उपायों की सूची दी थी जो सरकार ने मुद्रास्फीति, विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति, में आपूर्ति पक्ष की समस्याओं से निपटने के लिए किए हैं। हां, आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक भारी वर्षा और बाढ़ आदि, जिन पर भी आरबीआई और सरकार के बीच चर्चा होती रहती है और सरकार कदम उठा रही है।

**मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:**

तो, क्या आप आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन से, जिस प्रकार सरकार कर रही है, संतुष्ट हैं?

**शक्तिकांत दास:**

आप मुझसे सरकार की कार्रवाई को रेटिंग देने के लिए कह रहे हैं, जो मैं नहीं करूंगा क्योंकि यह एक निरंतर परस्पर-संवाद की प्रक्रिया है। सरकार ने कई उपाय किए हैं और प्रक्रिया ऐसे ही चलती है।

**मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:**

क्या मैं एलसीआर पर एक और प्रश्न जोड़ सकता हूँ?

**शक्तिकांत दास:**

एलसीआर के संबंध में, हमने इसे अभी तक पेश नहीं किया है, न ही लागू किया है। यह अभी भी मसौदे के चरण में है, इसलिए जब टिप्पणियां आएंगी, तो हम उनकी जांच करेंगे।

**मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:**

अब प्रश्न यह है कि यह अतिरिक्त 5% क्यों? क्या आपको कोई ऐसा संकेत या सिग्नल मिला है कि सिलिकॉन वैली जैसी समस्याएं हो सकती हैं? क्या कोई चिंता थी क्योंकि अतिरिक्त 5% बहुत अधिक है?

**शक्तिकांत दास:**

मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि दूसरे प्रश्नों की स्पष्टता प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद द्विपक्षीय रूप से की जा सकती है, लेकिन चूंकि आपने इसे कैमरे के सामने कह दिया है, इसलिए मैं उप गवर्नर राजेश्वर राव से इस प्रश्न का उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

**एम. राजेश्वर राव:**

धन्यवाद गवर्नर। मुझे लगता है कि गवर्नर ने ठीक ही संकेत दिया है कि यह इस चरण में एक मसौदा परिपत्र है। एलसीआर दिशानिर्देश 2014 में जारी किए गए थे, इसलिए उस समय प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण आदि में हो रहे वर्तमान विकास को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा की आवश्यकता थी। अतः, उन सभी पहलुओं को समाहित किया गया है और मसौदा दिशानिर्देशों को सार्वजनिक डोमेन में रख दिया गया है। अतः, हम सार्वजनिक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करेंगे और फिर अंतिम निर्णय लेंगे कि क्या किया जाना चाहिए।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। महोदय, आपकी अनुमति से कुछ और प्रश्न। अगला, हम पीटीआई के श्री आशीष अगाशे को प्रश्न देंगे।

**आशीष अगाशे, पीटीआई:**

महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपने वैश्विक आउटेज (वैश्विक स्तर पर सेवाओं का ठप होना) और हमने उससे कैसे निपटा, इसके बारे में बात की। साथ ही, हाल ही में एक ही संस्था पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, हमने देखा कि कई छोटे घरेलू ऋणदाताओं और ग्राहकों को लेन-देन करने में, साधारण भुगतान-लिंकड लेन-देन करने में कठिनाई हो रही थी। महोदय, वास्तव में क्या होता है? हम इससे कैसे बच सकते हैं? आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं?

**शक्तिकांत दास:**

मुझे लगता है कि उपगवर्नर स्वामिनाथन इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

**स्वामीनाथन जे.:**

यह सही है। एक आईटी सेवा प्रदाता से प्रभाव पड़ा क्योंकि यह एक तीसरे पक्ष की सेवा प्रदाता प्रणाली थी जो प्रभावित हुई थी। संयोगवश, वह संस्था कई अन्य छोटे बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी इसी प्रकार की तीसरे पक्ष की सेवाएं प्रदान कर रही थी। चूंकि जोखिम के अन्य प्रणालियों तक संचरित होने की संभावना थी, इसलिए एक अग्र-सक्रिय उपाय के रूप में, उन्हें भुगतान प्रणाली से बंद कर दिया गया। यह एनपीसीआई द्वारा एक सक्रिय उपाय के रूप में किया गया था, और यह लगभग 3-4 दिनों तक चला। अपनी आंतरिक मूल कारण विश्लेषण

के अलावा, एक बाहरी पक्ष द्वारा भी अध्ययन किया गया। कुछ उपचारात्मक उपायों की सिफारिश की गई है। उन्हें लागू किया जा रहा है। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके कारण हम बार-बार उचित आपदा बहाली और कारोबार निरंतरता योजनाओं पर जोर देते हैं, जिसे इस भाषण में भी दोहराया गया है कि सभी सेवा प्रदाताओं के पास अपनी आपदा बहाली और व्यापार निरंतरता योजना मजबूत होनी चाहिए और बैंकों के पास भी वैकल्पिक मार्ग होने चाहिए जिनके माध्यम से वे कार्य कर सकें। अतः, ये ऐसी चीजें हैं जो विकसित होती रहती हैं लेकिन हम निगरानी करते हैं और सलाह प्रदान करते हैं। सीएसआईटी ने इस घटना के चलते यह सलाह जारी कर दी है कि बैंक अपनी प्रणालियों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और अपनी व्यापार निरंतरता योजनाओं को कैसे लागू कर सकते हैं। हम ग्राहकों की असुविधा को कम से कम करने को सुनिश्चित करने के संदर्भ में संस्थाओं की सहायता करते रहेंगे।

#### **शक्तिकांत दास:**

मैं बस एक छोटा सा पूरक जोड़ना चाहूंगा। देखिए, एनपीसीआई द्वारा उस विशिष्ट सेवा प्रदाता के शामिल होने वाले सभी स्थानों पर आगे के लेन-देन को रोकने का कार्य समस्या को अलग-थलग करने के लिए किया गया था, और यदि यह नहीं किया जाता, तो इसका प्रभाव पूरी प्रणाली पर पड़ सकता था जो कहीं अधिक महंगा पड़ सकता था। अतः, उस समस्या को अलग-थलग करके निपटाना आवश्यक था, और जैसा कि उपगवर्नर कह रहे हैं कि आरबीआई की सीएसआईटी टीम ने पहले ही इसके विवरण में जांच की है और उचित कार्रवाई की गई है।

#### **पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। अगला, हम द हिंदू के श्री ललतेंदु मिश्रा को प्रश्न देंगे।

#### **ललतेंदु मिश्रा, द हिंदू:**

शुभ अपराह्न, गवर्नर। अनुप के प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए, आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा इस सुझाव के बारे में आपका क्या विचार है कि खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को ढांचे से अलग कर दिया जाना चाहिए?

#### **शक्तिकांत दास:**

नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। ये सभी संस्थागत विचार हैं। और जैसा कि मैंने कहा, एनएसओ सर्वेक्षण चल रहा है। और जो डेटा सामने आएगा, उसके आधार पर, सरकार और रिजर्व बैंक के बीच उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि एनएसओ सर्वेक्षण क्या डेटा और क्या चित्र प्रस्तुत करता है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। हम मनीकंट्रोल की सुश्री हंसिनी कार्तिक को प्रश्न देंगे।

**हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:**

शुभ अपराह्न, महोदय। मेरा प्रश्न बेज़मानती ऋणों से संबंधित है। अपेक्षा है कि वित्त वर्ष 2026 में, परियोजना ऋणों से संबंधित मुद्दों और एलसीआर के संबंध में विनियामक ढांचे में थोड़ा और कसाव हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में, क्या आप असुरक्षित ऋणों और एनबीएफसी को ऋण देने पर जोखिम भार पर पुनर्विचार करेंगे, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि पिछले वर्ष नवंबर में जारी किया गया परिपत्र, जिसका उद्देश्य इन ऋणों को रोकना था, कहीं न कहीं अपना काम करना शुरू कर रहा है। तो, क्या आप इसे एक वर्ष या इससे अधिक समय तक प्रतीक्षा करना चाहेंगे, यह देखने के लिए कि यह प्रणाली में कितना प्रभाव डाल रहा है और इसकी समीक्षा करें? क्या आप इस पर कोई मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, महोदय?

**शक्तिकांत दास:**

मुझे लगता है कि आप (उपगवर्नर एस जे) उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

**स्वामीनाथन जे.:**

देखिए, 23 नवंबर के उपाय अपना अभिप्रेत प्रभाव डाल रहे हैं। हम आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन इस समय यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अब तक केवल दो-तीन तिमाहियों का डेटा आया है। अतः, हम निगरानी करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे आगे बढ़ता है। दूसरी बात, विकास दर में कमी आई है लेकिन फिर भी यह अच्छी गति बनाए हुए है। जब हमने यह लागू किया था, तब इनमें से कुछ खंडों में वर्ष-दर-वर्ष विकास दर लगभग 30% थी, जो वर्तमान में 15% से 16% की वर्ष-दर-वर्ष दर पर चल रही है। मेरा मानना है कि यह समग्र ऋण विकास के रुझान के अनुरूप है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इस समय इसमें कमी लाने या संशोधन करने की आवश्यकता है। हालांकि, हम आने वाले डेटा पर नजर रखते रहेंगे।

कसने की बात बाकी बची वस्तुओं के संदर्भ में दूसरे मुद्दे पर आते हुए, मेरा मानना है कि वे सभी इस समय मसौदा दिशानिर्देशों के चरण में हैं। एक बार जब सभी प्रतिक्रियाएं एकत्रित हो जाएंगी, तो उस समय जोखिम भार की जांच की जा सकती है, न कि अभी। तीसरा, निश्चित रूप से, व्यक्तिगत खंड के संदर्भ में, आप यह सराहना करेंगे कि हम केवल कोविड-पूर्व स्तर को वापस लाए हैं। हमने वास्तव में इसे बढ़ाया नहीं है। कोविड काल में, कठिन स्थिति से निपटने के लिए व्यक्तिगत खंड की कुछ श्रेणियों पर जोखिम भार कम किया गया था। इसलिए, हमने नवंबर 2023 में जो किया, वह केवल उसे पुराने स्तर पर वापस लाना था। अतः, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बढ़ाया गया हो और जिसके लिए इस समय

संशोधन की आवश्यकता हो। लेकिन हम आपका सुझाव लेते हैं। हम आने वाले डेटा पर नजर रखेंगे और यथावश्यक कदम उठाएंगे।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। अगला, हम द मिंट के श्री शायन घोष को प्रश्न देंगे।

**शायन घोष, द मिंट:**

गवर्नर, आपने हाल ही में प्रणाली में 'म्यूल अकाउंट्स' (फर्जी/ठगी वाले खाते) के बारे में बात की है। क्या आप हमें कुछ अंतर्दृष्टि दे सकते हैं कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, ये किस प्रकार के खाते हैं, और यदि आप इन म्यूल अकाउंट्स के संदर्भ में यह भी बता सकें कि प्रणाली में कितने पाए गए हैं, तो उस पर कुछ संख्यात्मक डेटा दे सकें?

**शक्तिकांत दास:**

नहीं, हमारे पास इसके लिए कोई तैयार डेटा उपलब्ध नहीं है। क्या आपके पास (उपगवर्नर एसजे) इस संबंध में कुछ है?

**स्वामीनाथन जे.:**

नहीं, हम संख्याओं के रूप में ऐसा डेटा नहीं रखते हैं। मूल रूप से, हम जो करते हैं वह केवाईसी प्रक्रिया, ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, लेन-देन निगरानी प्रक्रिया और सक्रिय जोखिम प्रबंधन उपायों के संदर्भ में सलाह पर पुनर्बल देना है। ये वे चीजें हैं जिन पर हम विनियमित संस्थाओं के साथ जोर देते रहेंगे ताकि ऐसे खातों के अस्तित्व में होने या धोखेबाजों द्वारा उनके उपयोग की संभावना को कम से कम किया जा सके। यही हम करेंगे। प्रविष्टियों की संख्या आदि और उन्हें अक्षम करना एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। हम समय-समय पर इनसे उत्पन्न जोखिमों को कम से कम सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, मंत्रालय और भागीदार बैंकों के साथ निकटता से काम करते हैं।

**शक्तिकांत दास:**

देखिए, बैंकों के पास अपनी लेन-देन निगरानी प्रणाली है। कुछ बहुत ही असामान्य विशिष्ट लेन-देन होते हैं। उदाहरण के लिए, एक कम मूल्य वाला बैंक खाता जहां लेन-देन बहुत कम मूल्य के रहे हों, अचानक यदि लेन-देन की आवृत्ति या राशि बढ़ जाती है। कई ऐसे मामलों में, लेन-देन रात के देर घंटों में किए जाते हैं। अतः, बैंकों के पास अब इसकी निगरानी करने के लिए प्रणालियां हैं, और हमने बैंकों को इसके प्रति संवेदनशील बनाया है। अधिकांश बैंकों के पास बैंकिंग प्रणाली में इस प्रकार के खातों के व्यवहार की निगरानी करने के लिए प्रणालियां स्थापित हैं और जहां आवश्यक हो, कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि उन्होंने (उप गवर्नर)

कहा, आरबीआई, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सरकार के संबंधित मंत्रालयों और निश्चित रूप से बैंकों के बीच निरंतर संवाद बना हुआ है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। अगला, हम एनडीटीवी प्रॉफिट के श्री विश्वनाथ नायर को प्रश्न देंगे।

**विश्वनाथ नायर, एनडीटीवी प्रॉफिट:**

गवर्नर, आपने सार्वजनिक भाषणों में दो बार बैंकों में खुदरा जमा वृद्धि के बारे में बात की है और उन्हें चेतावनी दी है कि यदि यह समस्या वर्तमान से बड़ी हो जाती है तो संरचनात्मक मुद्दे हो सकते हैं। या तो वे अधिक रिटेल जमा आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने में असमर्थ हैं या इच्छुक नहीं हैं। लेकिन क्या इस स्थिति में सलाह और चेतावनियों के अलावा आरबीआई द्वारा कुछ और किया जा सकता है? क्या आप किसी भी समय बैंकों को वास्तव में उन जमाओं को आकर्षित करने के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं? मैं विशिष्ट निर्देश की बात कर रहा हूँ।

**शक्तिकांत दास:**

नहीं, यह फिर से बैंकों पर निर्भर है कि वे अपना निर्णय स्वयं लें। हम बैंकों के निर्णय और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों पर भरोसा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणालियां आज बहुत अधिक मजबूत हो गई हैं, इसलिए हम बैंकों के लिए सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हां, पर्यवेक्षक स्तर पर, निरंतर चर्चा होती रहती है। हमारे पर्यवेक्षक नियमित अंतराल पर बैंकों के साथ संवाद करते हैं। मेरे स्तर पर, मैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों दोनों के सीईओ के साथ बैठकें करता हूँ। ऐसे मुद्दे चर्चा के लिए आते हैं। वास्तव में, पिछली बैठक में जो हमने लगभग एक महीने पहले की थी, यह विषय सूचीबद्ध विषयों में से एक था। हमने चर्चा की, अपने विचार साझा किए और अब यह बैंकों पर निर्भर है कि वे वास्तव में आवश्यक उपाय करें। जब और जहां आवश्यक होगा, आरबीआई कार्रवाई करेगा। कृपया ध्यान दें कि आपको यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आरबीआई चलनिधि प्रबंधन पर कार्रवाई करेगा। बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में सभी आने वाले डेटा की निगरानी की जाती है और हमें ऐसे मुद्दों से निपटना पड़ता है यदि वे उत्पन्न होते हैं।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद। महोदय, अंतिम दो प्रश्न। अतः, हम दूरदर्शन की सुश्री श्यामा मिश्रा को प्रश्न देंगे।

### **श्यामा मिश्रा, दूरदर्शन:**

धन्यवाद महोदय। महोदय, विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति का मुद्रास्फीति पर आप क्या प्रभाव देखते हैं? क्या आगे चलकर यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है?

### **शक्तिकांत दास:**

नहीं, हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। यह स्थिति मोटे तौर पर 2-3 स्थानों तक सीमित थी। केरल में यह एक विशेष जिला था। हिमाचल में भी कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए। और जाहिर है कि इनका सब्जियों की कीमतों या आपूर्ति में व्यवधान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम उनकी निगरानी कर रहे हैं और कुछ प्रभाव अस्थायी होंगे, इसलिए इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। इसका व्यापक स्तर पर मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी हम निगरानी कर रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा।

वर्तमान में, हमारे पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मानसून दीर्घकालिक औसत से लगभग 7% अधिक है - क्योंकि यह हर दो दिन या इसी अवधि में हो रहा है। और खरीफ की बुवाई में तेजी आई है। और यह न भूलें कि मानसून सीजन के दूसरे हिस्से में 'ला निना' की स्थिति बनने का पूर्वानुमान है और जलाशयों के स्तर भी अभी बहुत अच्छे हैं। अतः, इसका खरीफ उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खरीफ का सकल बोया गया क्षेत्र भी बढ़ गया है, इसलिए हमें इसका खरीफ उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। और मिट्टी में नमी की मात्रा में सुधार के कारण, इसका रबी उत्पादन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अतः, ये वे चीजें हैं जिनकी हम लगातार निगरानी कर रहे हैं, और हम इससे निपटेंगे।

### **पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। मैं अपने अगले प्रश्न के लिए निकेई के श्री रयोसुके हनादा को आमंत्रित करता हूं।

### **रयोसुके हनादा, निकेई:**

नमस्ते । मैं सरकारी बांड के बारे में पूछना चाहता हूं। पिछले महीने के अंत में, आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी बांड खरीदने का एक नया मार्ग घोषित किया था। अधिक विशिष्ट रूप से, मेरा प्रश्न 'पूर्णतः सुलभ मार्ग' (एफएआर) के तहत 10 वर्ष और 30 वर्षीय सरकारी बांडों को बाहर रखने के बारे में है। क्या आप इस निर्णय के उद्देश्य और संदर्भ के बारे में बता सकते हैं और आपको लगता है कि इसका वैश्विक निवेशक भावना और भारतीय बाजार के लिए निवेश वरीयता पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

### शक्तिकांत दास:

मुझे लगता है कि इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर उपगवर्नर माइकल पात्रा ने पहले ही दे दिया है, लेकिन जहां तक भारत के प्रति वैश्विक निवेशक भावना का सवाल है, यह बहुत अधिक बनी हुई है। और मैंने अपने वक्तव्य में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह के संबंध में डेटा प्रस्तुत किया है। अतः, हमारा आकलन है कि भारत के संबंध में वैश्विक निवेशकों का विश्वास बहुत सकारात्मक है, जैसा कि एफपीआई/एफडीआई प्रवाह से परिलक्षित होता है। और यह भी तथ्य है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के संबंध में, भारत की जीडीपी वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च रहने की उम्मीद है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे आईएमएफ ने भी भारत के लिए अपनी वृद्धि अनुमान को 6.8% से बढ़ाकर 7.0% कर दिया है। अतः, मुझे लगता है कि समग्र रूप से भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बना हुआ है।

### पुनीत पंचोली:

अंतिम प्रश्न हम इन्फॉर्मिस्ट मीडिया की सुश्री प्रतिज्ञा वाजपेयी से लेंगे।

### प्रतिज्ञा वाजपेयी, इन्फॉर्मिस्ट मीडिया:

नमस्कार। डॉ. पात्रा ने अभी कहा कि चलनिधि की स्थितियां आरबीआई की मौद्रिक नीति का रुख दर्शाती हैं। पिछले कुछ महीनों में, हमने देखा है कि चलनिधि की स्थितियों में ऐसा उतार-चढ़ाव आया है कि ओवरनाइट दरें 25 आधार अंक कम हो गई हैं। तो, हम आरबीआई के चलनिधि प्रबंधन को वर्तमान स्थिति के संदर्भ में कैसे पढ़ें, जो कि इस पूरी अवधि में अपरिवर्तित रही है? और क्या आरबीआई की खुले बाजार की कार्रवाई बिक्री भी मूल चलनिधि को कम करने के उद्देश्य से हैं?

### माइकल डी. पात्रा:

अतः, यदि आप कुछ समय पहले की स्थिति को याद करें, तो एक विशिष्ट चलनिधि स्थिति थी जहां सरकारी शेष राशि जमा हो रही थी और खर्च नहीं हो रहा था, जिससे चलनिधि तंग हो गई थी। अब, हम चलनिधि स्थितियों में बहुत बेहतर संतुलन देख रहे हैं। अतः, हम जैसा कि क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, मांग दर (कॉल रेट) को बीच में रख रहे हैं। यह कॉरिडोर के केंद्र में है, और सामान्यतः हम इसे वहीं रखना चाहते हैं। हमारी सभी कार्रवाइयां इसे बनाए रखने के उद्देश्य से हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, कॉल रेट हमारा परिचालन लक्ष्य है, यह मौद्रिक नीति की स्थिति को दर्शाता है, और निभावकारी स्थिति को हटा लेना जारी रखने की है।

**पुनीत पंचोली:**

धन्यवाद महोदय। अतः, हम आपकी अनुमति से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करेंगे। इसे संवादात्मक बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए रिजर्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।

**शक्तिकांत दास:**

धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।